

औद्योगिक रूग्णता की समस्या का अध्ययन

डॉ. प्रतिमा बनर्जी*

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - आधुनिक समय में सुदृढ़ औद्योगिक आधार देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिये आवश्यक है परन्तु विगत वर्षों में औद्योगिक रूग्णता की समस्या गम्भीर होती जा रही है। इस समस्या से न केवल औद्योगिक क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है वरन् सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कारण यह है कि औद्योगिक रूग्णता से उत्पादन, आय, रोजगार, बैंकिंग एवं बीमा कम्पनियों आदि सभी पर खराब प्रभाव पड़ता है। यह समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में परिलक्षित हो रही है। कम्पनी (संशोधन) विधेयक 2002 के अनुसार किसी कम्पनी को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी तब कहा जायेगा जब विगत लगातार चार वर्षों में से किसी एक या अधिक वर्षों में वित्तीय वर्ष के अन्त में इसकी संचित हानि इसकी नेट वर्थ का 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा/ अथवा जो लगातार तीन तिमाहियों तक अपने ऋणदाताओं को अपनी देयताओं का भुगतान करने में असफल रही हो। प्रो० नन्दकर्णी के अनुसार- 'एक निवेशक के लिए वह इकाई रूग्ण है जो लाभांश नहीं देती, एक उद्योगपति के लिए जो लाभ नहीं अर्जित कर रही है और बन्द होने के कगार पर है, एक बैंक की दृष्टि से वह इकाई रूग्ण है जिसने गत वर्ष नगद हानि उठाई हो एवं चालू तथा आने वाले वर्षों में भी उसकी पुनरावृत्ति की सम्भावना हो।'

रूग्णता के लक्षण - औद्योगिक रूग्णता के लक्षण निम्नलिखित हैं:-

1. यदि किसी औद्योगिक इकाई की बिक्री में क्रमशः कमी हो। रूग्ण उपक्रम द्वारा रोकड़ डिस्काउंट में वृद्धि करके, विक्रय में वृद्धि करने के असफल प्रयत्न, उदार-उधार नीति तथा शिथिल वसूली आदि।
2. रोकड़ प्रबंध की समस्याएं हो अर्थात् रोकड़ निर्गमों में स्थिरता किन्तु रोकड़ आगमों में निरन्तर गिरावट हो।
3. पूँजी-ढाँचे के दोष परिलक्षित हो जैसे स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों के मूल्यों में कमी, बाजार के नजरों में उपक्रम के विशुद्ध मूल्यांकन में गिरावट आदि।
4. कार्यशील पूँजी प्रबंध के स्तर में गिरावट हो। व्यवसाय के चालू अनुपातों, शीघ्र अनुपातों में धीरे-धीरे लगातार गिरावट, प्राप्ति में वृद्धि तथा दोषपूर्ण काल-क्रम सूची, माल के स्टॉक में वृद्धि आदि।
5. वैधानिक दायित्वों की पूर्ति में कमी हो अर्थात् निर्बल रोकड़ स्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के करों, भविष्य निधि एवं ग्रेज्युटी की कटौतियों, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौतियों घोषित लाभांशों एवं ऋणों पर देयमूल्य एवं ब्याज की किश्तों की अदायगी में असमान्य विलम्ब एवं त्रुटि दिखाई दें।
6. बैंक ग्राहक सम्बन्धों में ह्रास हो, जैसे अधिकारियों पर अधिक निर्भरता,

रोकड़ साख के भुगतान में अनियमितताएं आदि।

7. सम्पत्ति-ढाँचे के दोष लक्षित हो जैसे स्थायी सम्पत्ति के उचित रख-रखाव मरम्मत देखरेख आदि की अवहेलना, दोषपूर्ण ह्रास नीति आदि।

रूग्णता के कारण- औद्योगिक रूग्णता के कारण निम्नलिखित हैं:-

1. वर्तमान में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती हुई गलाकाट प्रतिस्पर्धा में मंदी के कारण बिना बिका हुआ माल काफी मात्रा में बचा रह जाता है। इससे उद्योगों को हानि होती है और धीरे-धीरे वे रूग्ण हो जाते हैं।
2. प्रवर्तकों के पास अनुभव का अभाव होना, परियोजनाओं का गलत चयन तथा त्रुटिपूर्ण परियोजना नियोजन आदि जन्मजात रूग्णता को जन्म देते हैं।
3. कई नई औद्योगिक इकाइयाँ अल्प पूँजीकरण का शिकार होती हैं। वित्त अल्पता एवं त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्ध भी औद्योगिक रूग्णता को जन्म देता है।
4. उद्योगों में अकुशल प्रबंधन भी एक बड़ी समस्या है। अप्रशिक्षित प्रबंधन वर्ग, उत्पादन, वित्त, विपणन एवं कर्मचारियों के बारे में जब गलत निर्णय ले लेता है तब एक समृद्धशाली व्यवसाय भी पतन के गर्त में चला जाता है।
5. औद्योगिक रूग्णता का एक कारण तकनीकी तत्व भी है जैसे- अप्रचलित या अनुपयुक्त तकनीक या पुरानी तकनीक।
6. जिन उद्योगों में आयातित कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, यदि वे ऐसे क्षेत्र में स्थापित हो जाती हैं जहाँ परिवहन सुविधाओं का अभाव है तो रूग्णता को बढ़ावा मिलता है।
7. औद्योगिक रूग्णता इस कारण भी उत्पन्न हो जाती है कि बड़ी परियोजनाओं को प्रारम्भ करने में काफी विलम्ब हो जाता है जिसके कारण साज-सज्जा, मशीन आदि की लागत में काफी वृद्धि हो जाती है और परियोजना की अनुमानित लागत काफी बढ़ जाती है।
8. बहुत से उपक्रम, स्वामियों की स्वार्थपरता एवं तीव्र मतभेदों के कारण भी रूग्ण हो जाते हैं।
9. आयात, निर्यात, औद्योगिक लाइसेन्स, कराधान आदि के बारे में सरकारी नीति अचानक बदल जाने से कोई भी स्वस्थ औद्योगिक इकाई जल्दी ही अस्वस्थ बन सकती है।
10. अनेक बीमार इकाइयों में औद्योगिक सम्बन्धों की दुर्बलता के कारण भी प्रायः तालाबन्दी तथा अन्य विविध प्रकार के संघर्ष पाये जाते हैं जो एक सीमा के बाद संस्था को अवनति के गर्त में ढकेल देते हैं।

11. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले परिवर्तनों के कारण भी औद्योगिक रूग्णता का प्रसार हो सकता है। विगत वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अनेक ऐसे परिवर्तन हुए हैं, जैसे – तेल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि, आयात-निर्यात पर रोक आदि।
12. भारत में औद्योगीकरण के साथ-साथ बिजली, कोयला व तेल की माँग में तीव्रता से वृद्धि हुई है जबकि उनकी पूर्ति में वृद्धि की दर उस अनुपात में नहीं बढ़ सकी है, फलतः शक्ति का संकट बना रहता है जिसके कारण उत्पादन का स्तर गिरने लगता है और उपक्रम को हानि होने लगती है।
13. औद्योगिक क्षेत्र में प्राविधि का विकास व हस्तान्तरण होता रहा है परन्तु कभी कभी नवीन आविष्कार अथवा नवीन खोज कुछ उत्पादनों को अप्रचलित एवं अनुपयुक्त बना देते हैं जिससे उनसे सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण हो जाती हैं।

रूग्णता के परिणाम—औद्योगिक रूग्णता के प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं:—

1. भारत जैसी अर्थव्यवस्था में जहाँ पूँजी जैसे संसाधनों का अभाव है, औद्योगिक इकाइयाँ जब रूग्ण होकर बंद हो जाती हैं तो राष्ट्र को काफी क्षति होती है।
2. औद्योगिक इकाइयों के रूग्ण हो जाने पर बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण की बकाया राशियाँ न प्राप्त होने की स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं जिससे बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को बहुत हानि उठानी पड़ी है।
3. औद्योगिक रूग्णता के कारण जहाँ एक ओर सरकार को राजस्व का घाटा होता है, वही दूसरी ओर सरकार को बड़ी मात्रा में वित्तीय भार उठाना पड़ता है।
4. देश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से सम्बद्ध श्रम संघ सदैव अस्वस्थ इकाइयों को बंद करने का विरोध करते हैं, इससे बड़े स्तर पर हड़तालें प्रारम्भ हो जाती हैं तथा उनका उत्पादन गिरता जाता है।
5. कई उद्योग, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और उनमें से एक प्रकृति के उद्योग, यदि रूग्ण हो जाते हैं तो निर्भर उद्योगों पर भी विपरीत असर पड़ता है और वे भी रूग्ण हो जाते हैं।
6. जब देश की कई औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण हो जाती हैं तो उनमें लगे हुये यंत्र, उपकरण तथा अन्य साधन बेकार हो जाते हैं। इससे न केवल उन इकाइयों का उत्पादन गिर जाता है अपितु विनियोजित भारी पूँजी के दुष्परिणाम के रूप में लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
7. केन्द्र एवं राज्य सरकारें घाटे की अर्थव्यवस्था को झेल रही हैं। ऐसी स्थिति में जब भी औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण हो जाती हैं तो उनमें से श्रमिकों/कर्मचारियों की छँटनी कर दी जाती है और लाखों कार्मिक बेरोजगार हो जाते हैं।

रूग्णता के सुधार हेतु सुझाव—औद्योगिक रूग्णता के सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं:—

1. रूग्ण इकाई को वित्तीय संस्थानों द्वारा रियायती वित्तीय सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
2. यदि इकाई पुरानी मशीनों के कारण रूग्ण है तो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराकर उनका आधुनिकीकरण किया जा सकता है।
3. यदि इकाई की रूग्णता का कारण कार्यशील पूँजी का अभाव अथवा दोषपूर्ण पूँजी संरचना है तो कम ब्याज दर पर कार्यशील पूँजी की

- व्यवस्था, पुराने बिलों की अदायगी की तिथियों में परिवर्तन और इन ऋणों की ब्याज दरों में कमी आदि उपायों द्वारा उन्हें इस संकट से उबारने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।
4. यदि औद्योगिक रूग्णता किसी विशिष्ट घटक के कारण नहीं बल्कि सामान्य वातावरण के कारण है जो सम्पूर्ण उद्योग में फैली हुई है तो बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अकेले कुछ नहीं कर सकते। ऐसी दशा में सरकारी एजेन्सी के सहयोग से ऐसे पैकेज उपाय, जिनमें रियायती वित्त के साथ करें व उत्पादन शुल्क में छूट आदि भी सम्मिलित हो, लिये जाने चाहिए।
5. चूँकि वित्तीय संस्थानों के साधनों की भी सीमा है, वे सभी रूग्ण इकाइयों को सहायता उपलब्ध नहीं करा सकते। अतः सरकार ने ऐसी वृहद इकाइयों को आयकर आदि में छूट देने की नीति को अपनाया है जो रूग्ण इकाइयों के संविलियन अथवा सम्मिश्रण के तैयार हों, इससे रूग्ण इकाइयों में विनियोजित वित्तीय संस्थानों के धन तथा श्रमिकों के रोजगार की रक्षा सम्भव होती है।
6. यदि किसी इकाई की रूग्णता का कारण कोई विशेष समस्या, यथा—कच्चे माल का अभाव, अनुपयुक्त टेक्नालॉजी, हड़ताल अथवा तालेबन्दी अथवा विद्युत का अभाव है तो ऐसी स्थिति में ये संस्थान सम्बन्धित सरकारी एजेन्सी से मिलकर अपने दीर्घकालीन अनुभव के आधार पर इन समस्याओं के समाधान का सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. यदि किसी इकाई की रूग्णता का कारण उसका आन्तरिक कुप्रबन्ध हो तो वित्तीय संस्थान बैंक एवं सरकार से सहायता लेकर ऐसी इकाई के प्रबन्ध में परिवर्तन कर सकते हैं। ये संस्थान अस्थाई तौर पर कुछ प्रबंध विशेषज्ञों की सेवाएँ इकाई को उपलब्ध करा सकते हैं।

उपसंहार—औद्योगिक रूग्णता समाज के लिये एक समस्या एवं अभिशाप है। औद्योगिक रूग्णता को केवल आर्थिक समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता क्योंकि अनेक सामाजिक पहलू भी इससे जुड़े हैं। यही कारण है कि सरकार इन उद्योगों को चालू करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास कर रही है। औद्योगिक रूग्णता को नियंत्रित करने और उन्हें विभिन्न प्रकार से सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अनेक विशिष्ट संस्थाएँ भी स्थापित की हैं जैसे—भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल आदि। रूग्ण उद्योगों को पुनः कार्य करने योग्य बनाने में व्यापारिक बैंक भी सहयोग करती हैं। रिजर्व बैंक द्वारा रूग्ण इकाइयों के बारे में समय समय पर 'निर्देशक सिद्धान्तों' का प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने औद्योगिक अस्वस्थता की समस्या के समाधान हेतु केन्द्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों को स्थायी रूप से यह दायित्व सौंपा है कि वे अपने अपने परिक्षेत्र में आने वाली औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता को रोकें और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:—

1. इंडियन बिजनेस इनवायरमेंट—रंजीत पपाचन
2. Essentials of Business Environment -K.Aswathappa
2. बिजनेस इकॉनामिक्स—डॉ. डी.के.दुबे, डॉ. एस.के.मिश्रा
3. व्यावसायिक पर्यावरण—वी.सी.सिंह
4. व्यावसायिक पर्यावरण—डॉ. जे.सी.वाष्णेय, डॉ.एस.सी.जैन
5. प्रतियोगिता दर्पण वार्षिकी, 2023